बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

○ वर्ष: 23 ○ अंक: 155 ○ नई दिल्ली ○ बुधवार 18 जून 2025 ○ प्रभात कालीन ○ मूल्य: 3 रूपया ○ पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

जी7 देशों की पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की अपील, लेकिन बोले- इस्राइल को आत्मरक्षा का अधिकार

ओटावा । जी7 देशों के नेताओं ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की अपील की, लेकिन साथ ही संयुक्त बयान में इस बात की पुष्टि भी की इस्राइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी जी7 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि हम जी7 देशों के नेता, पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता का समर्थन करते हैं। साथ ही हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस्राइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। हम इस्राइल की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। साथ ही हम आम नागरिकों की सुरक्षा के भी पक्षधर हैं। जी7 देशों के संयुक्त बयान में ईरान को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा और आतंकवाद का स्त्रोत बताया गया है। जी7 देशों ने भी कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता।

जजों की नियुक्ति को नियंत्रित करना चाहती सरकार, जस्टिस वर्मा मामले में सिब्बल का गंभीर आरोप

नई दिल्ली । राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार जस्टिस वर्मा के महाभियोग के जरिए जजों की नियुक्ति पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। सिब्बल ने कहा कि सरकार कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म कर नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लागू करना चाहती है। वरिष्ठ वकील ने आरोप लगाया कि सरकार जस्टिस वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के मामले में पक्षपात पूर्व कार्रवाई कर रही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस शेखर यादव पर बीते साल सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप है और उनके खिलाफ एक विपक्षी सांसद ने राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन राज्यसभा सभापति ने अभी तक उसकी मंजूरी नहीं दी है।

गौरतलब है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास पर बीते साल मार्च में आग लग गई थी। उस दौरान उनके घर से बड़ी मात्रा में जले हुए नोट बरामद हुए थे। इसके बाद जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद उच्च न्यायालय तबादला कर दिया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की जांच में भी जस्टिस वर्मा को दोषी पाया था। हालांकि जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बीते दिनों बताया था कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार की इच्छा कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने और जजों की नियुक्ति पर नियंत्रित स्थापित करने की है। जस्टिस वर्मा के पक्ष में बोलते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि %मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वे एक बेहतरीन जज हैं, जिनके सामने मैंने बहस की है। आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वकील के पूछ सकते हैं।

आप इलाहाबाद में उनके बारे में पूछ सकते हैं। राज्यसभा सांसद ने सवाल उठाते हुए पूछा कि एक जज के खिलाफ सबूत नहीं हैं तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि जिनके खिलाफ सबूत हैं और मामला पब्लिक डोमेन में है तो भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कपिल सिब्बल ने सरकार पर जस्टिस शेखर यादव को बचाने का आरोप लगाया। कॉलेजियम सिस्टम वह प्रक्रिया है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं। इसमें सरकार का दखल नहीं होता। कॉलेजियम भारत के चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम जजों का एक समूह है। ये पांच लोग मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। ये नियुक्तियाँ हाई कोर्ट से की जाती हैं और सीधे तौर पर भी किसी अनुभवी वकील को भी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सलाह से होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। साल 2014 में सरकार संविधान में 99वां संशोधन करके नेशनल ज्यूडिशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन (एनजेएसी) अधिनियम लेकर आई। इसमें सरकार ने कहा कि चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट- हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की जगह अब एनजेएसी के प्रावधानों के तहत काम हो। इस कमिशन में छह लोगों को सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है जिनमें, चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया, केंद्रीय क़ानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम जस्टिस और दो विशेषज्ञ शामिल होंगे। दो विशेषज्ञों का चयन चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के तीन सदस्यीय पैनल को करना था। यह प्रावधान भी किया गया कि दो विशेषज्ञ सदस्य हर तीन साल पर बदलते रहेंगे। हालांकि साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

कांग्रेस का खटा खट मॉडल देश के विकास के लिए बड़ी चुनौती, विपक्षी पार्टी पर भाजपा का तंज

नई दिल्ली । बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने जनगणना कराने का फैसला किया है. प्रेस रिलीज में साफ कहा गया कि जनगणना के साथ-साथ आजाद भारत के इतिहास में पहली बार सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके पीछे हमारा उद्देश्य सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों का सम्मान और अंतिम छोर पर खड़ी जातियों का उत्थान है। लेकिन इंडी गठबंधन और कांग्रेस केवल अपने परिवार के उत्थान के बारे में ही सोचते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमारी सोच और उनकी सोच में बुनियादी फर्क है। हम सभी जातियों की पहचान, सम्मान और उत्थान के लिए समर्पित हैं...जाति जनगणना की अधिसूचना केंद्र द्वारा की जाती है।

राज्य जाति जनगणना नहीं कर सकता। इसलिए, वे जो राज्य की अधिसूचना दिखा रहे हैं, उससे केवल सर्वेक्षण हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां-जहां कांग्रेस सत्ता में आती है, उनका खटा खट मॉडल देश के विकास के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हाल ही में सैटेलाइट फिल्मों में दिखाए जाने के बाद भी पाकिस्तान के एयरबेसों की तबाही नजर नहीं आई। उन्हें CAA के नोटिफिकेशन में उत्पीड़न शब्द नजर नहीं आया था। इसी दृष्टिदोष के चलते कांग्रेस को इस बार भी चीजें नजर नहीं आईं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने भारत की जनगणना कराने का निर्णय लिया, और इसके बाद जो भी प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें स्पष्ट रुप से कहा गया कि जनगणना के साथ सामाजिक, आर्थिक मूल्यांकन होगा और जाति जनगणना स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगी। त्रिवेदी ने कहा कि परन्तु वो पार्टी, जिसने 1951 में स्वतंत्र भारत में जातिगण जनगणना को रुकवाने का काम किया था। जिन्होंने पिछड़ों के हक को मारने के लिए काका कालेलकर की रिपोर्ट को नहीं लागू होने दिया था, आज वो अचानक जो कहने का प्रयास करते हैं और जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनकी राजनीति का तत्व सामने आ जाता है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के द्वारा होता है, राज्य सरकार जातिगत जनगणना कर ही नहीं सकती है, तो आप (कांग्रेस) किस राज्य के नोटिफिकेशन को दिखा रहे हैं। राज्य सिर्फ सर्वे कर सकती है। सर्वे को नोटिफाई करने का प्रोसीजर अलग है।

ठगी का नया पैंतरा : कोरोना में हुआ घाटा तो स्कूल संचालक बन गया साइबर ठग, दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से ऐसे दबोचा

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस के साइबर थाना टीम ने राजस्थान के सीकर से एक स्कूल संचालक को गिरफ्तार किया है। स्कूल संचालक ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर महिला से 29 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया था। आरोपी 44 वर्षीय चोथमल सैनी को पुलिस कई साल से तलाश कर रही थी, उस पर जिले में पहले भी दो ठगी के मामले दर्ज हैं। चोथमल सैनी के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोबाइल बरामद किया है। आरोपी ने बताया कि कोविड काल में वह घाटे में चला गया था, जिसके बाद वह साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि साइबर थाना पुलिस को पीड़ित एसश्रीवास्तव ने अपने साथ ठगी की शिकायत दी।उन्होंने शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से एक वेबसाइट की जानकारी दी। यह वेबसाइट पार्ट-टाइम जॉब उपलब्ध कराने के साथ ही ऑनलाइन निवेश में मदद करती थी। पीड़ित ने आरोपियों द्वारा दिए गए खातों में निवेश के नाम पर पैस जमा करना शुरू किया। पीड़िता जितना पैसा जमा करती वेबसाइट पर मौजूद उसके अकाउंट में वह पैसा दिखाई देता। पीड़ित ने कूल 29 लाख रुपए जमा किए, जो लाभ के बाद कई करोड़ में बदल गया। लेकिन जब पीड़िता ने वेबसाइट पर मौजूद अपने अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश की तो वह पैसा नहीं निकाल सकी। जिसके बाद उसे अपने साथ ठगी होने की जानकारी हुई। पीड़ित ने तुंरत पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक की टीम ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों की तकनीकी निगरानी, डिजिटल फुटप्रिंट और मनी ट्रेल का विश्लेषण किया। जिससे पता चला कि आरोपी जिस व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे थे वह फर्जी पहचान पर लिए गए नम्बर थे। आरोपियों ने पूरे भारत से

करंट अकाउंट चला रहे लोगों से कमीशन के आधार पर उनके अकाउंट किराए पर लिए थे। जिनमें पीड़िता से पैसा जमा कराए गए थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि सभी खाताधारकों को जयपुर व सीकर के अलग अलग होटलों में बुलाया गया था। पुलिस ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीकर से पुलिस ने चोथमल सैनी को वारदात में इस्तेमाल मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी चोथमल सैनी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसे अपना स्कूल चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी क्योंकि वह कोविड काल से घाटे में था और कमीशन के आधार पर धोखेबाजों को बैंक खाता उपलब्ध कराता था। संदिग्ध ठगी की गई राशि/भुगतान को विभिन्न खातों में जमा करवाते हैं और भुगतान को नकद में लेते हैं। पुलिस आरोपी की निशानदेही पर अब उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयाा कर रही है।

सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की सेहत में सुधार, खान-पान पर विशेष नजर

दिल्ली । पेट से जुड़ी समस्या को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को रविवार शाम को सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी की सेहत में सुधार बताया जा रहा है, लेकिन अभी उनकी अस्पताल से छुट्टी की तारीख तय नहीं की गई है। अस्पताल के चेयरमैन अजय स्वरूप ने बताया कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और सेहत में सुधार है, वे पेट के संक्रमण से उबर रही हैं। उनके खान-पान पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है और वे निगरानी में हैं। एहतियात के तौर पर, उनकी छुट्टी की तारीख अभी तय नहीं की गई है। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य और खान-पान पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। दरअसल नौ जून को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने इसी अस्पताल में मेडिकल चेक-अप कराया था। चेक-अप से दो दिन पहले, उच्च रक्तचाप की शिकायत के बाद शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में उनकी कुछ जांच की गई थी।

याचिकाकर्ताओं का दावा, बाटला हाउस में डीडीए के विध्वंस नोटिस पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली । हाईकोर्ट ने ओखला स्थित बाटला हाउस क्षेत्र में कथित अवैध संपत्तियों के विध्वंस के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने याचिकाकर्ताओं और डीडीए के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। याचिकाएं हीना परवीन, जीनत कौसर, रुखसाना बेगम और निहाल फातिमा सहित अन्य की ओर से दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि डीडीए ने सामान्य नोटिस जारी किया है, जिसमें खसरा नंबर 279 में आने वाली संपत्तियों का स्पष्ट डिमार्केशन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस खसरे में सभी संपत्तियां अवैध नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे लंबे समय से इन संपत्तियों में रह रहे हैं और इन्हें बिल्डर से खरीदा था। उनके वकील ने बताया कि खसरा नंबर 279 में कुल 34 बीघा जमीन है, लेकिन विध्वंस का आदेश केवल 2 बीघा और 10 बिस्वा के लिए है। उन्होंने कहा कि कुछ याचिकाकर्ता 1980-82 से वहां रह रहे हैं। उनके दस्तावेज उर्दू और फारसी में थे, जिनका बाद में अनुवाद कराया गया। वहीं, डीडीए की ओर से पेश वकील ने याचिकाओं का विरोध किया। डीडीए ने निहाल फातिमा और अन्य के मामले में दावा किया कि उनके पास कोई शीर्षक दस्तावेज नहीं हैं और जो दस्तावेज पेश किए गए, वे कार्यवाही के दौरान तैयार किए गए।

विदेश यात्रा की वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए वाड्रा; मनी लॉन्ड्रिंग केस में होनी थी पूछताछ

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से समन भेजे जाने के बाद भी कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा आज उनके सामने पेश नहीं होंगे। उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक, वे विदेश यात्रा पर हैं और वापस आने के बाद जांच में शामिल होंगे। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए वाड्रा को अपने दफ्तर बुलाया था। मामला ब्रिटेन के रहने वाले हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ा है। मामले की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की जा रही है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा को 10 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने तब यह कहते हुए पेशी से इनकार कर दिया था कि उन्हें 9 जून को फ्लू जैसे लक्षण थे और उन्होंने कोविड टेस्ट कराया है। उनके

वकील ने उस समय कहा था कि वाड्रा समन से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे देश से बाहर जाने से पहले या बाद में कभी भी ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। वाड्रा से ईडी ने अप्रैल में तीन दिन लगातार पूछताछ की थी। ये पूछताछ हरियाणा में 2008 की एक जमीन डील में कथित गड़बड़ियों से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी। रॉबर्ट वाड्रा ईडी की जांच के तहत कुल तीन मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में फंसे हुए हैं। संजय भंडारी एक हथियार डीलर हैं जो 2016 में दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद लंदन भाग गए थे। हाल ही में एक ब्रिटिश अदालत ने भारत सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें भंडारी के प्रत्यर्पण से जुड़े मामले को ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद भंडारी को भारत लाने की संभावना लगभग खत्म हो गई है ईडी ने 2023 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि भंडारी ने 2009 में लंदन में एक मकान खरीदा और उसे रॉबर्ट वाड्रा के निर्देशानुसार रिनोवेट कराया। एजेंसी का दावा है कि इस रिनोवेशन के लिए पैसा वाड्रा ने दिया था। रॉबर्ट वाड्रा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनकी लंदन में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। उन्होंने इन आरोपों लेकर कहा कि उन्हें राजनीतिक मकसद के तहत परेशान किया जा रहा है।

एडीजीपी की गिरफ्तारी मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर हुई अपील

नई दिल्ली । तमिलनाडु के एडीजीपी की गिरफ्तारी के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस उज्जल भुइंया और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि वे बुधवार को याचिका पर सुनवाई करेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में तमिलनाडु के एडीजीपी एचएम जयराम को अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि सोमवार को तमिलनाडु उच्च न्यायालय ने राज्य के एडीजीपी एचएम जयराम को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। यह गिरफ्तारी अपहरण से जुड़े मामले में हुई थी। उच्च न्यायालय के जस्टिस पी वेलमुरुगन की पीठ ने विधायक एम जगन मूर्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजीपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। लक्ष्मी नाम की एक महिला ने अदालत में अपील कर बताया कि उसके बड़े बेटे ने एक लड़की से परिवार की सहमति के बिना प्रेम विवाह किया। इसके बाद लड़की के घरवाले कुछ बदमाशों के साथ उसके बड़े बेटे की तलाश में उनके घर पहुंचे। बड़े बेटे और बहू के न मिलने पर आरोपी छोटे बेटे को अपने साथ ले गए और मारपीट के बाद बेटे को एक होटल के पास घायल अवस्था में छोड़ गए। आरोप है कि छोटे बेटे को जिस वाहन से छोड़ा गया, वह एडीजीपी का सरकारी वाहन था। आरोप है कि विधायक ने पूरी घटना की साजिश रची। इसके बाद कोर्ट ने एडीजीपी और विधायक दोनों को उच्च न्यायालय में पेश होने को कहा और सुनवाई के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जज ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि दो आरोपियों ने अपने कबूलनामे में एडीजीपी का नाम लिया है, ऐसे में कानून के मुताबिक एडीजीपी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उच्च न्यायालय इस मामले पर 26 जून को सुनवाई करेगा।

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, नोएडा-गुरुग्राम में बरसे बदरा; गर्मी से मिली लोगों को राहत

नई दिल्ली। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में दोपहर करीब दो बजे मौसम पूरी तरह से बदल गया। आसमान में घने बादल छा गए। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं नोएडा और गुरुग्राम में बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने मौसम को और सुहावना बना दिया है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को मौसम ने बड़ी राहत दी। सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही और दोपहर बाद हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने शहर को सुहावना बना दिया। मौसम विभाग के अनुसार, तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। जिले के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश सुबह से ही देखी जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। ऐसे में गर्मी से परेशान लोगों को आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मौसम का यह बदला मिजाज लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आया है और फिज़ा को खुशनुमा बना दिया है। वहीं में दोपहर दो बजे के करीब मौसम अचानक से बदल गया। तेज हवाएं और बिजली कड़की और इसके बाद बारिश शुरू हो गई। फरीदाबाद में अचानक बदले मौसम के मिजाज ने शहर का माहौल खुशनुमा बना दिया। वहीं तापमान में गिरावट से भीषण गर्मी से कुछ राहत महसूस की गई। गाजियाबाद में भी बारिश हो रही है। इसके अलावा बुलंदशहर में तेज बारिश हुई।

मरीज के पेट में चम्मच: 30 मिनट में निकाली आठ सेमी लंबी स्पून, दुर्लभ मामले में डॉक्टरों ने किया कमाल

नई दिल्ली । शालीमार बाग स्थित निजी अस्पताल में एक 30-वर्षीय पुरुष की दुर्लभ और असामान्य मेडिकल इमरजेंसी की गई। डॉ. रमेश गर्ग, सीनियर डायरेक्टर एवं एचओडी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के डॉक्टरों की टीम ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी प्रक्रिया को 30 मिनट में किया गया और मरीज को अगले ही दिन स्थिर हालत में अस्पताल से छुट्टी दी गई। मरीज की शुरूआती जांच के बाद इमरजेंसी विभाग को रेफर किया गया था। जब मरीज यहां आए थे तो उनकी हालत स्थिर दिखायी दे रही थी। यहां उनके पेट के एक्स-रे समेत तत्काल डायग्नॉस्टिक इमेजिंग की गई, जिससे पता चला कि उनकी आंत के ऊपरी हिस्से में एक धातु का चम्मच फंसा हुआ था। मरीज की एनेस्थीसिया में तत्काल इमरजेंसी अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की गई। सर्जिकल टीम ने फोरसेप की मदद से सावधानीपूर्वक मरीज के पेट से चम्मच निकाला। इस सर्जरी के बाद उन्हें 24 घंटे तक निगरानी में रखा गया। इस दौरान वह पूरी तरह स्थिर थे और उन्हें बिना किसी जटिलता के हेल्दी कंडीशन में डिस्चार्ज किया गया। डॉ. रमेश गर्ग ने बताया कि काफी दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण मामला था। चम्मच जैसी किसी धातु की वस्तु को निगलने से काफी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, खासतौर पर यदि वह छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में फंस जाए तो यह वाकई खतरनाक हो सकता है। ऐसे में समय पर डायग्नॉसिस और इंटरवेंशन काफी महत्वपूर्ण होता है। हमारी टीम ने एनेस्थीसिया के साथ इमरजेंसी अपर जीआई एंडोस्कोपी की और बेहद सटीकता के साथ 8 से.मी. लंबा चम्मच निकाला और इस प्रक्रिया में कोई आंतरिक चोट नहीं पहुंची। सर्जरी के बाद मरीज पर कड़ी नज़र रखी गई और उन्हें स्थिर अवस्था में डिस्चार्ज किया गया। इस मामले ने जटिल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इमरजेंसी में तुरंत फैसला लेने और मल्टीडिसीप्लीनरी टीमों के बीच तालमेल के महत्व को रेखांकित किया।

दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन

नई दिल्ली । दिल्ली में मंगलवार (17 जून) को रेखा गुप्ता सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया. अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया. ये 33 आयुष्मान मंदिर राजधानी दिल्ली की पुरानी डिस्पेंसरी या सरकार की खाली पड़ी इमारतों को मॉडिफाई कर तैयार किए गए हैं, और इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करके एक आधुनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में बदला गया है. शालीमार बाग और तीस हजारी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया. वहीं दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा में बने नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज सिंह ने किया. विकासपुरी में बना आरोग्य मंदिर एक बारात घर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला कर बनाया गया है और यह एक आधुनिक मिनी हेल्थ सेंटर जैसा बना है.

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्या है सुविधाएं?

भाजपा सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सुबह से शाम तक दो डॉक्टर मौजूद रहेंगे. साथ ही फार्मेसी के लिए अलग कमरा, मलहम पट्टी, टीकाकरण के लिए अलग रूम और कोल्ड स्टोरेज और एक लैब भी स्थित है, जिसमें डायबिटीज़, डेंगू, मलेरिया, HIV और लीवर टेस्ट समेत 10 प्रकार की जांचें तुरंत हो सकती हैं. 81 से ज्यादा ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाता है और रिपोर्ट बाहर से आती है. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की अगर मोहल्ला क्लिनिक से सुविधाओं की तुलना की जाए, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मरीजों के लिए बैठने की पर्याप्त जगह है, जबकि मोहल्ला क्लिनिक में जगह सीमित रहती है. जहाँ आरोग्य

मंदिर में फार्मेसी, नर्सिंग और टीकाकरण के लिए अलग-अलग कमरे हैं, वहीं मोहल्ला क्लिनिक में एक ही हॉल में मरीज के बैठने की व्यवस्था है और फार्मेसी भी इसी छोटे से हाल में है जबकि अंदर तुरंत जांच के लिए लैब नहीं है और ना ही टीकाकरण की व्यवस्था मोहल्ला क्लिनिक में है. इसके अलावा जहां आरोग्य मंदिर में परमानेंट डॉक्टर और स्टाफ हैं, वहीं मोहल्ला क्लिनिक में संविदा पर कार्यरत डॉक्टर और स्टाफ होते हैं. स्थानीय निवासी राम जीवन और सुषमा के मुताबिक आरोग्य मंदिर आने से उन्हें काफ़ी आराम होगा और अब प्राइवेट अस्पताल के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा.

डॉक्टर्स ने क्या कहा?

न्यूज़ से बात करते हुए आरोग्य मंदिर की मेडिकल ऑफिसर डॉ. मीना वर्षणेय ने बताया कि उद्घाटन आज हुआ है, लेकिन चूंकि पहले उद्घाटन 14 जून को होना था, तो 3 दिन पहले ही इलाज शुरू हो गया था और हर रोज 200 से ज़्यादा मरीज विकासपुरी विधानसभा के इस आरोग्य मंदिर में इलाज करवा रहे हैं. विकासपुरी के मोहल्ला क्लिनिक में तैनात डॉ आकाश के मुताबिक, मोहल्ला क्लिनिक में हर रोज इलाज करवाने आने वालो की संख्या लगभग 70 के आसपास है और उनकी बीजेपी सरकार से मांग है कि मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को परमानेंट किया जाए. बीजेपी जहां इन स्वास्थ्य केंद्रों को अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने पुराने मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी को रंग-रोगन कर नया नाम दे दिया है.

पंकज सिंह ने बताया प्लान

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह महज नाम बदलने की राजनीति है. वहीं बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह का दावा है कि यह मॉडल दिल्ली में स्वास्थ्य क्रांति लाने वाला है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने न्यूज़ से बातचीत में कहा, हमारा लक्ष्य इन आरोग्य मंदिरों में बेड डालकर इन्हें डे केयर सेंटर में बदलना है, ताकि बड़े अस्पतालों का बोझ कम किया जा सके. बीजेपी सरकार का वादा है कि फरवरी 2026 तक दिल्ली में कुल 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे. आज शुरू किए गए 33 केंद्र उसी दिशा में पहला कदम है, साथ ही हर आरोग्य मंदिर में क्यूआर कोड आधारित शिकायत प्रणाली भी शुरू की गई है, ताकि लोग अपनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचा सकें.

बिना रिश्वत व सिफारिश से हुई भर्ती मॉडल को सभी राज्यों ने अपनाना समय की मांग

वैश्विक स्तरपर भ्रष्टाचार रूपी महामारी का डंक पूरी दुनियाँ का हर देश झेल रहा है जिसके उपाय रूपी वैक्सीन का आविष्कार शायद अभी किसी देश ने नहीं किया है,परंतु उपायों पर काम ज़रूर चल रहा है,अगर मन में संकल्प हो,व दिल मेंज़ज्बा लेकर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना है तो, मेरा मानना है कि डंके की चोट पर सरकारी नौकरियों में न खर्ची न पर्ची, पारदर्शिता के साथ बिना रिश्वत व सिफारिश के साथ भारती करना होगा जिसमें पीएम से लेकर सीएम तक व गृहमंत्री से लेकर अंतिम स्टेज के कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग करना होगा। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रविवार 15 जून 2025 को मैं देर शाम से टीवी चैनलों इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया से लगातार टच में रहकर यूपी के लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान स्थल पर बड़े पैमाने पर चल रहे 60244 अभ्यर्थियों के जॉइनिंग लेटर सौंपने का समारोह चल रहा था जिसपर मीडिया के माध्यम से मेरी पूरी नजर लगी हुई थी, उसमें माननीय केंद्रीय गृहमंत्री ने दिल को छू लेने वालीबात कही कि यहां 60244 अभ्यर्थी बैठे हैं, हिम्मत से कह रहा हूं कि किसी को भी एक रूपए रिश्वत नहीं देनी पड़ी,बस! यही बात और यही मॉडल मैं एडवोकेशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र, चाहता हूं कि पूरे देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाए जो, माननीय पीएम और गृहमंत्री ही कर सकते हैं,सैल्यूट सर।चूंकि आज देश के सामने इतनी बढ़ी भर्ती व पारदर्शिता की गारंटी वाली मिसाल कायम हुई है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे न खर्ची न पर्ची पारदर्शिता के साथ बिना रिश्वत व सिफारिश से हुई भर्ती मॉडल को सभी राज्यों ने अपनाना समय की मांग है। साथियों बात अगर हम लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान पर 15 जून 2025 को चल रहे नौकरी जॉइनिंग लेटर सौंपने का समारोह की करें तो,यूपी में 60,244 चयनित सिपाहियों को जॉइनिंग लेटर दिए गए। इनमें से 15 को केंद्रीय गृहमंत्री और सीएम ने लेटर बांटे। बाकियों को समारोह स्थल पर दिए गए। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ, जब इतने बड़े पैमाने पर जॉइनिंग लेटर बांटे गए।चयनित सिपाहियों को 1,300 बसों से लखनऊ लाया गया।गृहमंत्री ने लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में कहा- यूपी सरकार में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। इस काम को आप सभी 60 हजार युवाओं को और आगे बढ़ाना है। अगले पांच सालों में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि किसी भी एफआई आर के बाद तीन साल के भीतर उसपर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा- पहले 11 राज्यों में नक्सलवाद हुआ करता था। पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां कीं। मेरी बात याद रखना, 31 मार्च, 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा।आगे बोले- बिना पर्ची, बिना खर्ची के हुई ये भर्ती रेखांकित करने योग्य है पिछली सरकारों में कई सारी भर्तियां भी हुई,परंतु मेरे सामने 60,244 अभ्यर्थी बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत के साथ कह रहा हूं कि किसी को एक रुपए की रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। भर्ती पारदर्शिता के साथ हुई है। न खर्ची, न पर्ची, नहीं, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं, और भ्रष्टाचार से भी नहीं। योग्यता के आधार पर 48 लाख आवेदन में से आपका चयन आपकी योग्यता के आधार पर हुआ है।सिपाही भर्ती में 12 हजार से अधिक बच्चियां हैं, जिनके चेहरे की मुस्कान और तेज देखकर काफी सुकून मिला है। गृहमंत्री ने कहा कि 60,244 युवाओं के लिए आज का दिन शुभ है।चयनित सिपाही बोले- एक भी रुपया घूस नहीं लगा। सीएम ने कहा- याद रखना ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, खून उतना कम बहेगा। गरीब से गरीब परिवार का बेटा सिपाही बना है। 8 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने यूपी के युवाओं को साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई, चाहे दलित हों, पिछड़े, महिला या पुरुष सबको बिना किसी भेदभाव के भर्ती का अवसर मिला है। उन्होंने अच्छी पुलिस साबित होने का संदेश दिया है। साथियों बात अगर हम 60244 अभ्यर्थियों के सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया की करें तो,48 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में 150 सवाल पूछे गए थे। हर सवाल के 2 नंबर तय थे, यानें कुल 300 नंबरों की परीक्षा हुई थी। माइनस मार्किंग भी थी,हर गलत सवाल पर 0.25 नंबर काटे गए।सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा के बाद 1,74,316 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। 10 से 27 फरवरी 2025 के बीचफिजिकल टेस्ट कराया गया,इसके बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर और आरक्षण नियमों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई। तीन महीने पहले, यानी 13 मार्च को फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया था।12,048 महिलाओं और 48,196 पुरुषों ने परीक्षा पास की थी। जिसके आधार पर अंतिम रिजल्ट निकला। साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार के डंक से अर्थव्यवस्था प्रभावित होकर विकास पर असर पड़ने की करें तो,भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थानों की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। 2005 में ट्रान्सपैरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक अध्ययन में दर्ज किया गया कि 62 पेर्सेंट से अधिक भारतीयों ने किसी न किसी समय पर नौकरी पाने के लिए एक सार्वजनिक अधिकारी को रिश्वत दी थी। 2008 में, एक अन्य रिपोर्ट ने दिखाया कि लगभग 50 पेर्सेंट भारतीयों को रिश्वत देने या सार्वजनिक कार्यालयों द्वारा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सम्पर्कों का उपयोग करने का प्रत्यक्ष अनुभव था। 2022 में उनके भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ने देश को 180 में से 85वें स्थान पर रखा,इसपैमाने पर जहां सबसे कम रैंक वाले देशों को सबसे ईमानदार सार्वजनिक क्षेत्र माना जाता है। सरकारी समाज कल्याण योजनाओं से धन की हेराफेरी करने वाले अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार में विभिन्न कारकों का योगदान है। उदाहरणों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटीअधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान शामिल हैं।भ्रष्टाचार के अन्य क्षेत्रों में भारत का ट्रकिंग उद्योग शामिल है,जो अंतर्राज्यीय राजमार्गों पर कई नियामकों और पुलिस बन्धों को वार्षिक अरबों रुपये की उत्कोच देने के लिए मजबूर है। साथियों बात अगर हम भारत के महाशक्ति बनने में भ्रष्टाचार भी एक कसौटी होने की करें तो, भारत के महाशक्ति बनने की सम्भावना का आकलन अमरीका एवं चीन की तुलना से किया जा सकता है। महाशक्ति बनने की पहली कसौटी तकनीकी नेतृत्व है। दूसरी कसौटी श्रम के मूल्य की है। महाशक्ति बनने के लिये श्रम का मूल्य कम रहना चाहिये। तब ही देश उपभोक्ता वस्तुओंका सस्ता उत्पादन कर पाता है और दूसरे देशों में उसका उत्पाद प्रवेश पाता है। चीन और भारत इस कसौटी पर अव्वल बैठते हैं जबकि अमरीका पिछड़ रहा है।तीसरी कसौटी शासन के खुलेपन की है। वह देश आगे बढ़ता है जिसके नागरिक खुले वातावरण में उद्यम से जुड़े नये उपाय क्रियान्वित करने के लिए आजाद होते हैं। बेड़ियों में जकड़े हुये अथवा पुलिस की तीखी नजर के साये में शोध, व्यापार अथवा अध्ययन कम ही पनपते हैं। भारत और अमरीका में यह खुलापन उपलब्ध है। चीन इस कसौटी पर पीछे पड़ जाता है। वहां नागरिक की रचनात्मक ऊर्जा पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण है।चौथी कसौटी भ्रष्टाचार की है। सरकार भ्रष्ट हो तो जनता की ऊर्जा भटक जाती है। देश की पूंजी का रिसाव हो जाता है। भ्रष्ट अधिकारी और नेता धन को स्विट्ज़रलैण्ड भेज देते हैं। ट्रान्सपेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा बनाई गई सूची में भारत को 84वां स्थान दिया गया है। पांचवीं कसौटी असमानता की है।

सम्पादकीय...

टेंपरेचर सैट करने से बात नहीं बनेगी

सरकार अब एयर कंडीशनर के तापमान सैट करने पर नियम लाने की तैयारी में है। एसी का टेंपरेचर 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज्यादा नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया में भी छा गया। आलोचकों का कहना है कि विदेश की नकल में ऐसा किया जा रहा है, जबकि वहां इमारतों को कूल रखने के नियम हैं। हाल के दिनों में घरों, कार्यालयों, होटलों व मॉल तक में एसी का उपयोग बेतहाशा बढ़ा है। जिसके चलते गर्मियों के पीक सीजन में बिजली की खपत चरम पर पहुंच जाती है। केंद्र सरकार योजना बना रही है कि घरों, होटलों व कार्यालयों में बीस डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच इस्तेमाल होने वाले इस उपकरण की कूलिंग रेंज को मानकीकृत किया जाए। नए दिशा-निर्देश लागू होने के बाद एसी निर्माताओं को बीस डिग्री से कम तापमान पर कूलिंग प्रदान करने वाले एसी बनाने से रोक दिया जाएगा। फिलहाल देश में जो एयर कंडीशनर आ रहे हैं उनमें तापमान की सैटिंग को 16 डिग्री या 18 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है। वहीं, इनमें अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। भारत में 40 डिग्री पर एसी की ठंडक भी कम हो जाती है। लोग एसी कितने पर रखें, यह उनकी मर्जी होनी चाहिए। वहीं, समर्थकों का कहना है कि इससे बिजली की बचत होगी। ये नियम घरों, ऑफिस, दुकानों और गाड़ियों में लगे एसी पर भी लागू होगा। ज्यादा एसी चलने और टेंपरेचर 16 डिग्री पर सैट करने से बिजली की खपत बढ़ रही है। यह बहस ऐसे समय में छिड़ी है, जब पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी से झुलस रहा है। जापान, इटली, स्पेन और साउथ कोरिया जैसे देशों में एसी के तापमान के सख्त नियम हैं। जापान में डिफॉल्ट सैटिंग 26 डिग्री है। इटली और स्पेन में 23 और 27 डिग्री है। अमेरिका का ऊर्जा मंत्रालय घरों पर एसी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रखने की अनुशंसा करता है। हालांकि, इसका फैसला वहां रहने वाले लोगों के विवेक पर छोड़ा गया है। चीन में पर्यावरण मंत्रालय एसी को गर्मियों के दौरान 26 डिग्री सेल्सियस से कम न करने और सर्दियों में 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर सैट न करने की अनुशंसा करता है। सिंगापुर में घरों से लेकर उद्यमों और दफ्तरों में भी 25 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा तापमान रखने के दिशा-निर्देश हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर के अनुसार, बढ़ते तापमान से एसी की डिमांड तेजी से बढ़ी है। लोगों को सही में कूलिंग की जरूरत भी है लेकिन अक्सर एसी को बहुत कम तापमान पर चलाया जाता है। इससे बिजली की बर्बादी होती है। बिजली बिल ज्यादा आता है और स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम भी हो सकते हैं। 2020 में इस पर एक सर्वे काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर की टीम ने किया था । उसमें पता चला कि 60 फीसदी भारतीय एसी यूजर्स अपने एयर कंडिशनर को 23 डिग्री या उससे कम तापमान पर सैट करते हैं। अगर एसी के तापमान को 18 डिग्री से हल्का-सा बढ़ाकर 20 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाए तो बिजली खपत को 12 फीसदी तक कम किया जा सकता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार की यह पहल बिजली बचाने और भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा है। इस बात में दो राय नहीं कि गर्मियों की तपिश से बचने के लिये लोग अपने एसी को बहुत कम तापमान पर चलाते हैं। इस प्रवृत्ति का बिजली ग्रिड पर दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। निश्चित रूप से इसके चलते बिजली कटौती की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, इस संकट का अकेला मुख्य समाधान एसी को बेहद कम तापमान पर चलाया जाना ही नहीं है। इसके अलावा अन्य कारक भी हैं। यह भी एक हकीकत है कि सरकारी व निजी कार्यालयों में एसी का उपयोग काफी लंबे समय तक अंधाधुंध ढंग से किया जाता है। यहां इसके उपयोग में किफायत बरतने की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। निस्संदेह, ऊर्जा मंत्रालय का ऊर्जा नियामक ब्यूरो, बिजली खपत कम करने वाले उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देता है लेकिन जब गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती बढ़ रही है तो तापमान बढ़ने पर बिजली की खपत अनिवार्य रूप से बढ़ने लगती है लेकिन इसका एकमात्र कारण एसी का बढ़ता उपयोग ही नहीं है। हमें खुद से सवाल पूछने की जरूरत है कि हमारे शहर इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? हम इस बढ़ते तापमान से नागरिकों को राहत क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अंधाधुंध-अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे निर्माण कार्य भी इसमें कम दोषी नहीं हैं। हमने चारों तरफ कंक्रीट के जंगल तो बना दिए लेकिन शहरों में हरियाली का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है जिससे हवा का प्राकृतिक प्रवाह भी बाधित हो रहा है। विकास के नाम पर जो सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ काटे जाते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति नये पेड़ लगाकर नहीं की जाती है। हमारी जीवनशैली बिजली की खपत को लगातार बढ़ा रही है। हम घरों को प्राकृतिक रूप से ठंडा बनाये रखने वाली भवन निर्माण तकनीक नहीं अपना रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, लोगों को कूलिंग चाहिए और यह अब लग्जरी नहीं जरूरत है। एसी के मानक तय करते हैं तो बिल्डिंग इस तरह की बननी चाहिए कि वह ठंडी रहे। जिन देशों में एसी के टेंपरेचर के मानक हैं, वहां बिल्डिंग को लेकर नियम बहुत सख्त हैं। दोनों तरफ ध्यान देकर मानक तय हो रहे हैं। इटली, जापान से गर्मी के मामले में भारत की तुलना नहीं हो सकती। यदि हमारे देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए तो सड़कों पर निजी वाहनों का उपयोग कम होने से वाहनों के गर्मी बढ़ाने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ाकर और पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करके हम तापमान को कम करने का प्रयास भी कर सकते हैं। कम तापमान पर एसी चलाने से घर के अंदर का माहौल इतना ठंडा हो जाता है कि लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। इससे ऊर्जा की बर्बादी और बढ़ जाती है। शोध में यह भी सामने आया है कि 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान अधिकतर लोगों के लिए आरामदायक होता है, खासकर जब कमरे में हवा और नमी का संतुलन बना रहे। इस नियम को लेकर जानकारों का मानना है कि यह बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इस नियम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बिजली की बचत होगी। एयर कंडीशनर एक्सपर्ट बताते हैं कि हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से बिजली की खपत लगभग 6 फीसदी तक कम हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले की एक स्टडी की मानें तो भारत में एसी के तापमान की रेंज सीमित स्तर पर तय करने से 2035 तक देश 60 गीगावॉट तक बिजली बचा सकती है। यानी भारत में इससे नए ऊर्जा संयंत्रों और ग्रिड सिस्टम के लिए संभावित 88 अरब डॉलर (करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये) के खर्च को बचाने में मदद मिलेगी। इससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

उत्तराखंड में हैलीकॉप्टर हादसों का बढ़ता खतरा...

जून महीने के तीसरे रविवार दिनभर हादसों की खबरें आती रही। सुबह केदारनाथ से लौट रहे हैलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आई। कहीं मकान गिर गए और कहीं पुल टूटने से कुछ लोगों की जान चली गई। हादसों के पीछे कारण भले ही अलग-अलग हो लेकिन आम लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई और पूरे के पूरे परिवार सदमे में आ गए। हादसे तभी होते हैं जब ऊपर से नीचे तक लापरवाही बरती जाती है। प्रशासन और प्रबंधन को जहां मौजूद रहना चाहिए वह कहीं दिखाई नहीं देते। निजी कम्पनियों का लोभ भी काफी हद तक हादसों के लिए जिम्मेदार होता है। उत्तराखंड में लगातार हो रहे हैलीकॉप्टर हादसों पर लगाम लग पाना मुश्किल दिख रहा है। तमाम हवाई सेवा नियमावली और सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद लगातार हवाई हादसे हो रहे हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के 45 दिनों के भीतर पांच हैलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं, इनमें क्रैश लैंडिंग और इमरजैंसी लैंडिंग भी शामिल है। इनमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 270 लोगों की मौत के बाद देश अभी पूरी तरह से उभर नहीं पाया। 30 अप्रैल से शुरू हुई उत्तराखंड चारधाम यात्रा के बाद लगातार हो रहे हैलीकॉप्टर क्रैश एक्सीडेंट से उत्तराखंड 'क्रैश कैपिटल' बन रहा है। 15 जून को गौरीकुंड में हुए हैलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब हैलीकॉप्टर केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर गुप्तकाशी के लिए उड़ा था लेकिन गौरीकुंड के पास ही मौसम खराब होने से हैलीकॉप्टर क्रैश हो गया और 7 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भी चारधाम यात्रा में अन्य संचालित हैलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त या क्रैश लैंडिंग हो चुकी है। 8 मई 2025 को उत्तरकाशी जिले में क्रिस्टल एविएशन का हैलीकॉप्टर गंगनानी के पास क्रैश हो गया था। ये हैलीकॉप्टर खरशाली से झाला जा रहा था। हैलीकॉप्टर में बैठे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के यात्री गंगोत्री धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया था। 7 जून को क्रिस्टल एविएशन के ही हैलीकॉप्टर की बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ धाम हेलीपैड के लिए उड़ान भरते हुए हाईवे पर क्रैश लैंडिंग हो गई थी। गनीमत रही कि इस क्रैश लैंडिंग में हैलीकॉप्टर में सवार और हाईवे पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। हालांकि इस क्रैश लैंडिंग से हैलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के साथ ही हाईवे पर खड़ी एक कार को भी नुक्सान पहुंचा था। इस हादसे के दौरान हैलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। घटना के बाद डीजीसीए ने क्रिस्टल एविएशन कंपनी के हैलीकॉप्टर संचालन पर अगले आदेश तक पाबंदी लगा दी थी, जो अभी भी जारी है। यह हादसे दिखाते हैं कि उड़ानों का परिचालन करने वाली विमानन कम्पनियों पर कोई अंकुश नहीं है।

एक दिन में उनके द्वारा संचालित की जाने वाली उड़ानों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। एक हैलीकॉप्टर में कितने यात्री सवार हो सकेंगे, किसी नियम का पालन नहीं किया जा रहा। एक के बाद एक हादसों से कोई सबक नहीं लिया जा रहा। उत्तराखंड में हैलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं। चारधाम में उड़ने वाले हैलीकॉप्टर सिंगल इंजन के हैं। दुर्गम और अतिसंवदेनशील पहाड़ियों में हैलीकॉप्टर को उड़ान भरनी पड़ती है। मौसम खराब होना भी दुर्घटना का बड़ा कारण बनता है। बिजनेस के लिए लगातर हैलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं। एसओपी का पालन नहीं किया जाता है। हैलीकॉप्टर की मेंटिनेंस भी नहीं के बराबर होती है। हैलीकॉप्टर की हो रही लगातार दुर्घटनाओं के बाद डीजीसीए और राज्य सरकार सख्त हुई है। राज्य में हैलीकॉप्टर सेवाओं और उड़ान के लिए जल्द देहरादून में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता था, अगर नियमों का कागजों की जगह कड़ाई से पालन करवाया जाता। ऐसे में सवाल न सिर्फ हैलीकॉप्टर कंपनियों पर है, बल्कि नियम बनाने वालों से भी पूछा जा रहा है। हर हादसे के बाद सख्त निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। गौरीकुंड हादसे के पीछे खराब मौसम को कारण बताया गया। हादसे में मारे गए पायलट भी बहुत अनुभवी थे लेकिन सवाल यह है कि खराब मौसम के बावजूद उड़ान की अनुमति क्यों दी गई। यह पहले ही पाया जा चुका है कि हैलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने वाली कम्पनियां निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही। लापरवाही करने पर इन कम्पनियों को पहले भी जुर्माना लगाया जा रहा है लेकिन इंसानी जीवन की कीमत जुर्माना नहीं हो सकता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए हैली सेवा पूर्ण रूप से बंद रखने और पायलटों के हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान अनुभवों की जांच समेत सभी हैली ऑपरेटरों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही पुन: हैलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उड़ानें संचालित करने वाली कम्पनियों की जांच ईमानदारी और गंभीरता से की जाए ताकि लोगों का अमूल्य जीवन बचाया जा सके। हैलीकॉप्टर हादसों में सीडीएस जनरल विपिन रावत, कांग्रेस नेता संजय गांधी, माधव राव सिंधिया, आंध्र के मुख्यमंत्री रहे राजशेखर रेड्डी, अरुणाचल के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी, जाने-माने व्यवसायी ओपी जिंदल की मौत हैलीकॉप्टर हादसों में ही हुई थी। अनेक नेताओं की जानें जा चुकी हैं लेकिन अफसोस हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते। अगर ऐसा ही होता रहा तो विमान सेवाएं अपनी साख और भरोसा पूरी तरह से खो देंगी।

हवाई सुरक्षा में भारत इतना फिसड्डी क्यों ?

अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के तत्काल बाद कई शुभचिंतकों और मित्रों ने बात करते हुए सलाह देने की मुद्रा में यह जरूर कहा कि आप बहुत ज्यादा हवाई यात्रा करते हैं। उन्होंने सीधे तो नहीं कहा लेकिन उनके कहने का मतलब विमानन सुरक्षा को लेकर ही था, मैंने उन्हें समझाया कि यह एक दुर्घटना है। वास्तव में हवाई यात्रा अब भी सबसे सुरक्षित माध्यम बना हुआ है। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह पता चलता है कि दुनिया के स्तर पर हवाई यात्रा में मरने की आशंका 1 करोड़ 10 लाख यात्रियों में से केवल एक होती है जबकि सड़क दुर्घटना में मरने की आशंका अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होती है। हवाई यात्रा के सुरक्षित होने को लेकर मैंने उन्हें कई और आंकड़े दिए। मसलन, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में पिछले साल 1 लाख 80 हजार लोगों की मौत हुई। भारत में ट्रेन यात्राओं में भी औसतन हर साल 20 हजार लोगों की मौतें होती हैं। इन आंकड़ों को देखें तो हवाई यात्रा बिल्कुल महफूज नजर आती है लेकिन कुछ सवाल मेरे मन को लगातार मथते रहते हैं। अहमदाबाद की हवाई दुर्घटना के बाद तो सवालों ने और भी उधम मचाना शुरू कर दिया है। विमान यात्रियों के आंकड़ों के पैमाने पर देखें तो भारत इस समय दुनिया में तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा यात्री अमेरिका में उड़ान भरते हैं और दूसरे क्रम पर चीन है। तीसरे नंबर पर भारत है, मार्च 2025 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में डोमेस्टिक यानी देश के अंदर हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 16 करोड़ 54 लाख तक पहुंच चुकी थी। वर्ष 2023-24 की तुलना में यह आंकड़ा 7.6 प्रतिशत ज्यादा है। यह आंकड़ा साल-दर-साल बढ़ते ही जाना है क्योंकि बहुत सारे छोटे शहरों में एयरपोर्ट होने के बावजूद विमान सेवाएं शुरू होने का इंतजार है। तो फिर हवाई यात्रा की सुरक्षा के मामले में भारत अभी भी इतना फिसड्डी क्यों हैं? मैं फिसड्डी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम 48 वें नंबर पर हैं। सामान्य रूप से इस बात पर हम भारतीय सुकून व्यक्त कर सकते हैं कि 2018 में हम 102 नंबर पर थे और 2022 में 48 वें नंबर पर आ गए थे लेकिन मेरा सवाल है कि जब हम हवाई यात्रियों की संख्या में इतना ऊपर हैं तो हमें सुरक्षा के मामले में भी उतना ही चाक-चौबंद होना चाहिए। बहुत पुराने नियमों को भारत सरकार ने 2024 में बदल दिया था। उससे बहुत फर्क पड़ने की संभावना है लेकिन छोटी-छोटी बातें बड़ी आशंकाओं को जन्म देती हैं। मैं नागपुर एयरपोर्ट का ही एक उदाहरण देता हूं, छत की सीलिंग का एक हिस्सा अचानक एक दिन गिर गया। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ लेकिन कुछ यात्रियों को चोटें जरूर आईं। विमानन क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि वहां हर चीज के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, तो फिर छत की सीलिंग कैसे गिरी? कहीं न कहीं निर्माण कार्य में गड़बड़ हुई थी। इस तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी एयर इंडिया का जो विमान अहमदाबाद से उड़ान भरते ही दुर्घटना का शिकार हो गया था उसके कारण तो अभी सामने आना बाकी हैं कि वास्तव में हुआ क्या? मगर उसी दिन, उसी विमान में दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा के दौरान एक यात्री ने जो वीडियो बनाया वह खतरनाक था। वीडियो में दिख रहा है कि कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। एसी नहीं चलने से यात्री परेशान हैं।

साइप्रस यात्रा के जरिए तुर्की को कूटनीतिक जवाब

उमेश चतुर्वेदी ।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई इतनी सटीक क्यों रही? पाकिस्तान की खुफिया सेवा इसे भांप क्यों नहीं पाई, पाकिस्तानी राजनेता और सेना क्यों भारतीय कार्रवाई का अंदाजा नहीं लगा पाए। सवाल खत्म होते ही प्रधानमंत्री ठठाकर हंस पड़े। हंसते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना और राजनीति भारत के विपक्षी दलों की ही तरह हैं। जिस तरह वे मेरे बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, कुछ उसी तरह पाकिस्तानी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। दिल्ली में केंद्रीय सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कदमों को देखिए। हर बार वे चौंकाते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब समूचा विपक्ष भारत सरकार की विदेश नीति की नाकामी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना लगा रहा था, प्रधानमंत्री ने साइप्रस की यात्रा करके देश को चौंका दिया है। भूमध्य सागर के द्वीपीय देश साइप्रस की यात्रा का अचानक से ऐलान होना और कनाडा जाते हुए रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस उतरना और वहां के शीर्ष नेताओं से मिलना भारतीय विदेश नीति का चौंकाऊं फैसला ही है। देश के शीर्ष नेताओं की विदेश यात्राएं अरसा पहले से तय होती हैं, उसकी जानकारी राजनीति के साथ ही पत्रकारिता को भी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा अचानक से हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा का 14 मई को अचानक ऐलान किया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया में प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स से बातचीत भी की। ऐसे में सवाल यह उठ सकता है कि साइप्रस की यह अचानक यात्रा क्यों ? इस सवाल के जवाब में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई घटनाओं की ओर लौटना होगा। याद कीजिए, तब पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन के जरिए सैकड़ों हमले किए थे। उन हमलों को बेशक भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। साइप्रस की यात्रा के लिए हमें उन हमलों में इस्तेमाल हुए ड्रोन को देखना होगा। पाकिस्तान ने जिन ड्रोन से हमले किए, ज्यादातर तुर्की में बने सोनगार ड्रोन थे। हवाई हमलों में तुर्की के इन ड्रोन को बेहद मारक माना जाता है। हालांकि वे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के सामने बेकार ही साबित हुए। कूटनीतिक हलकों को पता है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने पाकिस्तान को उपलब्ध कराया। अर्दोआन ने पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का साथ दिया। इतना ही नहीं, भारत ने जब इस बात को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने रखा तो अर्दोआन ने ट्वीटर पर 'पाकिस्तान-तुर्की दोस्ती जिंदाबाद' लिखकर एक तरह से भारत के आरोप को साबित कर दिया। इसे भारत को मुंह चिढ़ाना भी कह सकते हैं। यह उस तुर्की का कदम था, जिसे भारत ने दो साल पहले दिल खोलकर मानवीय आधार पर सहयोग दिया था। छह फरवरी 2023 को तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, उस झटके में तुर्की में 53 हजार लोगों की मौत हो गई थी, हजारों लोग घायल हो गए थे। जान-माल के भारी नुकसान के बाद भारत ने मानवीय सहायता के साथ ही विशेषज्ञों की टीम के साथ बचाव दल भेजा था। राहत के तुर्की पहुंचने वाली टीमों में भारत की टीम भी शामिल थी। तुर्की के राष्ट्रपति ने जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से दोस्ती को जगजाहिर किया तो उसे भारत के लोगों ने भारत के लिए मुंह चिढ़ाना माना। रही-सही कसर पूरी हुई मई के आखिर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की तुर्की की यात्रा से। तब भारत के सामने अर्दोआन के रूख को लेकर कोई गुंजाइश ही नहीं रही। तुर्की को लेकर भारतीय समुदाय की सोच अब भी ऐसी ही है। ऐसा नहीं कि पहली बार तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए ऐसा कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के पक्ष में अर्दोआन सहयोगी भूमिका पेश करते रहे हैं। इन वजहों से तुर्की को लेकर भारत में गुस्सा भी बहुत रहा है। कश्मीर के मसले पर तुर्की हर बार पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरा भारत के उसी गुस्से की अभिव्यक्ति और भारत को मुंह चिढ़ाने के अर्दोआन के प्रयासों का जवाब माना जा सकता है। इसकी वजह है कि साइप्रस और तुर्की के बीच जारी बरसों पुराना विवाद। साइप्रस में यूनानी और तुर्की मूल के लोग रहते हैं। तुर्की के दोनों समुदायों में नस्ली आधार पर विवाद रहा है। साइप्रस में साल 1974 में तत्कालीन सरकार के खिलाफ यूनानी मूल के आतंकी समूहों ने तख्तापलट की कोशिश की। इसे तुर्की ने अपने लोगों के खिलाफ युद्ध माना। इसके बाद तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया। इस दौरान तुर्की की सेनाओं ने साइप्रस के दूसरे नंबर के मशहूर शहर वरोशा पर कब्जा कर लिया। यह शहर अपने बहुमंजिला भवनों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहां पूरे साल सैलानी आते रहते थे। लेकिन जब से तुर्की के कब्जे में यह शहर है, सैलानियों के लिए तरस रहा है। तुर्की की सेना के 35 हजार जवान यहां तैनात हैं। इसके बाद से एक तरह से यह द्वीपीय देश दो हिस्सों में बंट गया है। तुर्की के कब्जे वाले इलाके को तुर्की ने राष्ट्र का दर्जा दे रखा है। दिलचस्प है कि इस राष्ट्र के अस्तित्व को तुर्की के अलावा कोई देश स्वीकार नहीं करता। साइप्रस यूरोपीय संघ का भी सदस्य है और एक जनवरी 2026 से वह संघ का अध्यक्ष बनने जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। भारत को उम्मीद है कि साइप्रस के अध्यक्ष रहते यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो जाएगा। साइप्रस ने कई मौकों पर भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की दावेदारी का समर्थन कर चुका है। मोदी ने साइप्रस जाकर दो संदेश देने की कोशिश की है। पहला संदेश तुर्की के लिए है। भारत ने जता दिया है कि वह साइप्रस को सहयोग देगा और साइप्रस से सहयोग लेगा। वैसे भी साइप्रस के आईटी उद्योग और पर्यटन में भारत के हजारों लोग कार्यरत हैं। साइप्रस स्थित भारतीय हाईकमीशन के मुताबिक साइप्रस में साढ़े ग्यारह हजार लोग रहते हैं। मोदी की साइप्रस यात्रा का दूसरा संदेश भारतीयों के लिए है। पहले भारत से बहुत सारे सैलानी तुर्की जाते थे, लेकिन अब वे साइप्रस जाएंगे। वैसे पाकिस्तान के सहयोग के खुलासे के बाद से ही तुर्की के लिए बुक टिकटों को भारतीयों ने कैंसल कराना शुरू कर दिया था।

मोदी की कोशिश साइप्रस को बढ़ाकर तुर्की की आर्थिक रीढ़ पर चोट पहुंचाना है। साथ ही तुर्की को संदेश देना है कि जरूरत पड़ने पर भारत तुर्की के खिलाफ कड़े कदम भी उठा सकता है। प्रधानमंत्री ने कनाडा जाते हुए साइप्रस की यात्रा से तुर्की को भी चौंकाया है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने 2021 में कहा था कि साइप्रस की जिम्मेदारी तुर्की की है। यानी एक तरह से वह साइप्रस के एकीकरण के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के खिलाफ हैं। हालांकि अर्दोआन के कदम का इजरायल कड़ा विरोध करता है। साइप्रस की मौजूदा सरकार के साथ इजरायल मजबूती से खड़ा है। जाहिर है कि तुर्की के कदम का इजरायल विरोध कर रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की यात्रा के बाद इजरायल, भारत और साइप्रस संबंधों को भी गति मिलने की संभावना है। दुनिया इन दिनों चीन के 'वन बेल्ट-वन रोड' के जवाब में मध्य पूर्व के देशों के साथ यूरोप 'इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर' यानी आईएमईसी पर काम कर रहा है। भारत की साइप्रस यात्रा इस कॉरीडोर में भारत की संभावनाओं की भी खोज करती है। साइप्रस जाने वाली पहली भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहीं, जिन्होंने 1983 में इस देश का दौरा किया था, इसके उन्नीस साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने साइप्रस की यात्रा की थी। इसके 23 साल बाद मोदी की यात्रा हो रही है। यह यात्रा तुर्की को जवाब भी है और भारत की यूरोपी संघ से सीधे कारोबारी संपर्क की कोशिश भी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08863)

7 दिवसीय समर कैंप का बच्चों ने उठाया लुत्फ

फतेहपुर।

बच्चों के शैक्षणिक और नैतिक विकास की दिशा में एक अनूठा प्रयास

आतिफ, सुन्दुस और मदीहा ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी को किया प्रभावित

स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इंडिया (एसआइओ) फतेहपुर यूनिट द्वारा आयोजित 7 दिवसीय समर कैंप का जोश और उत्साह के साथ समापन हुआ।

यह शिविर 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षा, तरबियत और व्यक्तित्व निर्माण को केंद्र में रखते हुए विभिन्न गतिविधियाँ कराई गईं, जिसमें सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। आतिफ, सुन्दुस और मदीहा ने हर सत्र में बढ़-चढ़ कर भाग लिया और अपनी प्रस्तुतियों से सभी को प्रभावित किया।

स्टडी सेंटर फतेहपुर में आयोजित इस्लामिक समर कैंप में शहर के अलग-अलग इलाकों से दर्जनों बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मार्गदर्शन देने हेतु जमाअत-ए-इस्लामी हिंद फतेहपुर के अध्यक्ष वफाउर रहमान, एसआइओ के ज़ोनल सेक्रेटरी आक़िब फालाही ने विशेष रूप से शिरकत की। वक्ताओं ने कहा कि इस्लाम केवल इबादत का मज़हब नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए एक मुकम्मल निज़ाम है, जिसमें इंसान के सोचने, बोलने, चलने, पढ़ने और

समाज से जुड़ने तक का तरीका सिखाया गया है। अगर बच्चे शुरू से इस इस्लामी तरीक़ा-ए-ज़िंदगी को समझ लें, तो वे न सिर्फ़ अच्छे मुसलमान, बल्कि अच्छे इन्सान भी बनेंगे। साथ ही शूरा मेम्बर अब्दुल्लाह शाहीमी ने विशेष सत्र में बच्चों को कैरियर गाइडेंस के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताईं और उन्हें अपने लक्ष्य को पहचान कर मेहनत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसी तरह मोनिस शाहिद ने एक प्रभावशाली सत्र में बच्चों और अभिभावकों को क़ुरआन की रौशनी में माता-पिता के अधिकार और भूमिका पर बेहतरीन अंदाज़ में समझाया, जिसे सभी ने सराहा। समर कैंप को सफल बनाने में सआद, उनैस, अज़ीम, उसैद, अयान, यासिर, अब्दुल्लाह सिद्दीकी, असदुल्लाह और अयान इलाही का विशेष योगदान रहा। इन सभी कार्यकर्ताओं ने कैंप की प्लानिंग, संचालन और बच्चों के साथ हर गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभाई।

एसआइओ फतेहपुर के यूनिट अध्यक्ष मोहम्मद उजैर खान ने बताया कि प्रत्येक दिन की शुरुआत तिलावत और हिफ्ज़ से होती थी, जिसके बाद इस्लामी इतिहास, अख़लाक, सीरत, सहाबा किराम की जीवनियाँ, इस्लामी तौर-तरीके, विज्ञान और इस्लाम तथा समाज में मुसलमानों की भूमिका जैसे विषयों पर रोचक सत्र हुए। बच्चों ने कला-क्राफ्ट, ग्रुप डिस्कशन, खेलकूद, क्विज़ और डिबेट जैसी गतिविधियों में भी उत्साह से भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह समर कैंप सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक कोशिश थी, बच्चों के दिलों में ईमान, इल्म और अख़लाक़ की लौ जलाने की। आगे कोशिश रहेगी कि हम बच्चों को एक ऐसा वातावरण दें जहां वे दीनी तालीम और दुनियावी तरक्की दोनों के साथ आगे बढ़ें। अभिभावकों का आभार जताते हुए कार्यक्रम का समापन किया। समापन से पूर्व बच्चों को प्रशस्ति पत्र व उपहार भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अभिभावकों ने कार्यक्रम की दिल से सराहना की।

एक नजर

समाजसेवियों द्वारा परिवारिक विवाद/मतभेद को समाप्त कराते हुए 02 परिवारों को टूटने से बचाया

*आपसी मतभेद को भूल खुशी-खुशी रहने को हुए तैयार

बांदा । पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में परिवार परामर्श केन्द्र बांदा पुलिस टीम और समाजसेवियों द्वारा परिवारिक आपसी झगड़े/मतभेद को समाप्त कराकर सुलह कराते हुए 02 परिवारों को टूटने से बचाया । गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली लक्ष्मी पत्नी अनिल व सोनम पत्नी संजय द्वारा पुलिस अधीक्षक बांदा को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था । जिस पर पुलिस परिवार परामर्श केंद्र की टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनो पक्षों को समझाया गया । दोनों पक्षो द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर परिवार परामर्श केंद्र की टीम द्वारा परिवार को आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी ।

बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिला सहारा, मंत्री बीएल वर्मा ने 377 लाभार्थियों को बांटे 2134 उपकरण, खुशी से खिले चेहरे

बरेली।

बुजुर्गों और दिव्यांगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए एक बड़ी पहल की गई। राजकीय इंटर कॉलेज ऑडिटोरियम में मंगलवार को एक कार्यक्रम में उन्हें मुफ्त सहायक उपकरण बांटे गए। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना और एडिप योजना के तहत हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने किया, उन्होंने कहा ये लोग कमजोर नहीं हैं, बस उन्हें थोड़ा सहारा चाहिए। ये उपकरण उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। दिसंबर 2024 और अप्रैल 2025 में जिले के अलग-अलग ब्लॉक में कैंप लगाकर कुल 2812 लोगों को चिन्हित किया गया था।

इनमें 2739 बुजुर्ग और 73 दिव्यांग शामिल हैं। इन सभी को करीब 2 करोड़ 26 लाख रुपये के उपकरण मुफ्त में दिए जा रहे हैं। वितरण 25 जून तक चलेगा। कार्यक्रम में लाभान्वित कुल 377 लाभार्थियों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए। जिसमे सिलिकॉन फोम तकिया 229, नी बेस 746, लम्बोसैक्रल बेल्ट 375, बैसाखी बड़ी 02, एलबो बैसाखी साइज-दो 06, छड़ी 10, समायोजक छड़ी 279, चेयर/स्टूल कमोड सहित 255, फोल्डिंग व्हील चेयर 63, फोल्डिंग वॉकर 32, टाईपोड 31, छड़ी (सीट सहित) 02, बीटीई (कान की मशीन) 104 सहित कुल 2134 उपकरण वितरण किये गये। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ), कानपुर द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, सांसद छत्रपाल गंगवार, महापौर डॉ0 उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, सदस्य विधान परिषद बहोरन लाल मौर्य, विधायक कैंट संजीव कुमार अग्रवाल, विधायक मीरगंज डीसी वर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा अधीर सक्सेना, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, एलिम्को के वरिष्ठ प्रबन्धक अनुपम प्रकाश एवं प्रबन्धक हरीश कुमार सहित संबंधित अधिकारी गण व अन्य महानुभाव गणमान्य एवं लाभार्थी उपस्थित रहे।

महापौर परिषद बैठक में बोले डॉ. उमेश गौतम - बिना अधिकार के नगर निगमों से रैंकिंग की अपेक्षा अनुचित

बरेली।

पंचकूला (हरियाणा) में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारिणी बैठक में बरेली के महापौर डॉ. उमेश गौतम ने नगर निगमों को सीमित अधिकार मिलने का मुद्दा राष्ट्रीय मंच पर उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश में संविधान का 74वां संशोधन पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक बरेली जैसे शहरों की तुलना इंदौर और अहमदाबाद जैसे शहरों से नहीं की जानी चाहिए। डॉ. गौतम ने कहा कि इंदौर, अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों में महापौर को ट्रैफिक, पीडब्ल्यूडी, विकास प्राधिकरण और नगर निगम जैसे विभागों पर अधिकार प्राप्त हैं। इसके चलते वे एकीकृत शहरी विकास कर पा रहे हैं। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के महापौरों के पास न अधिकार हैं न पर्याप्त संसाधन, जिससे कार्यों में बाधा आती है। उन्होंने कहा कि जब महापौर के पास जरूरी विभागों का नियंत्रण ही नहीं है, तो स्वच्छता या स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार महापौर परिषद के सदस्य अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे।

ज्ञापन में मांग की जाएगी कि संविधान का 74वां संशोधन सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाए और नगर निगमों को बराबर अधिकार दिए जाएं। साथ ही जब तक यह व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक स्वच्छता सर्वेक्षण जैसी रैंकिंग में अंतर किया जाए। डॉ. उमेश गौतम ने कहा कि बरेली के स्कूली बच्चे भी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर आमजन की आवाज पहुंचाएंगे। बैठक में यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों के महापौरों ने भाग लिया और समान अधिकारों की मांग पर सहमति जताई।

उप अलम कमेटी के पदाधिकारियों को मिला प्रमाण पत्र

फतेहपुर। ताजिया व अलम इंनतेजामिया कमेटी ने गठित उप अलम कमेटी के अध्यक्ष व संरक्षक और सभी सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किया। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों में उप अलम कमेटी के संरक्षक परवेज खान, अध्यक्ष मो0 नईम अंसारी व सदस्य रियाज अहमद नसीम अहमद महफूज जमाल उद्दीन समीर अहमद इम्तियाज अहमद आदि रहे। इस मौके पर ताजिया व अलम इंतेजामिया कमेटी के अध्यक्ष चैधरी मोईन राईन जनरल सेक्रेटरी वारिस उद्दीन वरिष्ठ उपाध्याय शब्बीर उपाध्यक्ष अब्दुल सलाम उर्फ बाउवा मीडिया प्रभारी कफील अहमद प्रचार मंत्री हाजी कासिम खजांची खुर्शीद आलम खलील खॉ इंतेजाम कार फरीद खॉ इब्राहिम शाह वरिष्ठ ताजियादार हाफिज अहमद संदेश वाहक रियाज अहमद काले खां आदि उपस्थित रहे।

भारी बारिश से कक्करईया वाला कब्रिस्तान में जलभराव, कब्रें खुलीं, तैरते दिखे शव

बरेली। रविवार रात हुई भारी बारिश के कारण सतीपुर रोड स्थित नबादा शेरवानी के कक्करईया वाला कब्रिस्तान में करीब 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई कब्रें धंस गईं और करीब 7 से 8 शव पानी में तैरते नजर आए। यह दृश्य देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। क्षेत्रवासियों ने तुरंत नगर निगम पार्षद और नगर नायुक्त को इसकी जानकारी दी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद कोई भी नगर निगम कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉ. अनीस बेग मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तत्काल महापौर डॉ. उमेश गौतम को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। महापौर ने मदद का आश्वासन तो दिया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी थी। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम की घोर लापरवाही पर नाराजगी जताई और मांग की कि जल्द से जल्द जलनिकासी और कब्रों की मरम्मत का कार्य कराया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की शर्मनाक स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।

नगर निगम की लापरवाही पर भड़के स्थानीय लोग, डॉ. अनीस बेग ने पहुंचकर जताई चिंता

प्रदीप मिश्रा के कथन पर भड़का चित्रांश समाज, बरेली में किया प्रदर्शन

बरेली। कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त जी के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से कायस्थ समाज में आक्रोश फैल गया है। इसी के विरोध में सोमवार को जय चित्रांश समाज के बैनर तले समाज के सैकड़ों लोग सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में एकत्र हुए और वहां से पैदल मार्च निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और कथावाचक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान डॉ. शिवानंद चित्रगुप्त महाराज ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त जी कायस्थ समाज के आराध्य हैं और उनकी निंदा पूरे समाज की धार्मिक भावनाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा पहले भी देवी-देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं। हाल ही में एक धार्मिक मंच से उन्होंने भगवान चित्रगुप्त जी के संबंध में जो अमर्यादित टिप्पणी की, वह बेहद निंदनीय है। समाज के सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कथावाचक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो यह आंदोलन देशव्यापी रूप ले सकता है। ज्ञापन देने वालों में महेंद्र कुमार सक्सेना कातिब, शैलेन्द्र, राजबहादुर सक्सेना, शिवांग सक्सेना,सुधीर भटनागर, अंकुर किशोर सक्सेना, डॉ. पवन सक्सेना, आलोक सक्सेना, सुशील सक्सेना, चित्रांश पुष्पेंद्र, विजय नारायण सक्सेना, नरेश सक्सेना समेत समाज के कई सदस्य शामिल रहे।

श्रावण में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से होगी निगरानी, एसएसपी ने दे दिए ये निर्देश

बरेली।

आगामी श्रावण माह में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर बरेली प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर कमर कस ली है। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में यात्रा मार्गों की पहचान और सुधार का काम युद्धस्तर पर जारी है। प्रशासन का उद्देश्य इस बार यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाना है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कांवड़ मार्गों की पहचान शुरू कर दी है। इसके तहत सड़कों की मरम्मत, साफ-सफाई, पानी की टंकियों की व्यवस्था और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस ने यात्रा मार्ग के उन स्थानों की पहचान कर ली है जो संवेदनशील माने जाते हैं। यहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही, ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से निगरानी कर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ ही कांवड़ यात्रा को निर्बाध और सुरक्षित बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग के साथ समन्वय किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे और ट्रैफिक को सुचारु रखने के लिए वैकल्पिक रूट भी तैयार हो रहे हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ियों के रूट, पड़ाव स्थल और संभावित भीड़भाड़ वाले स्थानों का डेटा तैयार किया जा रहा है। प्रशासन स्थानीय धर्मगुरुओं, समाजसेवियों और गणमान्य नागरिकों से भी संवाद कर रहा है ताकि यात्रा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। जल्द ही प्रशासन विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करेगा, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जाएगी।

हिरनही के मिनी स्टेडियम में ग्रामीणों ने किया योग

जटहा बाजार विकास खण्ड विशुनपुरा के हिरनही स्थित मिनी स्टेडियम परिसर में मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की उपस्थिति से आयोजन को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। सामूहिक योगाभ्यास में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और योग गुरुओं के निर्देशन में विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान क्रियाएं कीं। आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण जनमानस को मानसिक एवं शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाना था। ग्राम प्रधान जयचन्द कुशवाहा ने कहा कि ÷योग भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है और इसके नियमित अभ्यास से हम न केवल स्वस्थ रह सकते हैं।

नौवे दिन भी एसडीएम विरोधी नारेबाजी के साथ हड़ताल पर रहे अधिवक्ता

कोराव प्रयागराज ।

तहसील कोराव में लगातार नौ दिन से उपजिलाधिकारी आकांक्षा सिंह के विरुद्ध चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल मंगलवार को भी एसडीएम विरोधी नारेबाजी के साथ जारी रही। बता दे कि तहसील कोराव में पिछले नौ दिन से लगातार एसडीएम की मनमानी और तानाशाही रवैये को लेकर चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही सुबह 11 बजे लामबंद अधिवक्ताओं ने बार एसोशिएशन तहसील कोराव के अध्यक्ष रामबहादुर सिंह और मंत्री लक्ष्मीकांत शुक्ल के नेतृत्व में एसडीएम विरोधी नारेबाजी करते हुए उपजिलाधिकारी कोर्ट का बहिष्कार किया बार अध्यक्ष ने कहा कि एसडीएम का ट्रांसफर जब तक नहीं होगा अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रहेगी इस दौरान बार एसोशिएशन के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार तिवारी, श्री कांत मिश्रा, देवकीनंदन मिश्रा, योगेन्द्र नाथ द्विवेदी, विनित मिश्रा, श्यामसुंदर तिवारी, शशिकांत कुशवाहा,सुनील कुमार पाण्डेय, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, राघवेंद्र मिश्र, अनूप मिश्रा, कैशलेश तिवारी महाकाल,रवि प्रकाश तिवारी, शिवानंद मिश्रा, भास्कर यादव, अखिल द्विवेदी, शशिकांत पाण्डेय, सर्वेश पाण्डेय, विजय बहादुर सिंह, विवेक गौतम, रामकृष्ण बिंद, सुनील तिवारी, यादवेंद्र यादव आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

नाबालिग से मारपीट का आरोप, महिला ने पुलिसकर्मियों और पड़ोसी पर लगाया गंभीर आरोप

बरेली।

पिता के निर्माणाधीन मकान को लेकर चल रहे विवाद में जबरन उठाया गया नाबालिग, चौकी में की गई मारपीट, एसएसपी से की शिकायत

बिहारीपुर क्षेत्र निवासी स्मिता रस्तोगी ने चौकी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके नाबालिग भाई को जबरन घर से उठाकर चौकी ले जाया गया और वहां उसके साथ मारपीट की गई। मामले को लेकर उन्होंने एसएसपी से लिखित शिकायत की है। शिकायतकर्ता स्मिता रस्तोगी ने बताया कि उनके पिता का मकान निर्माणाधीन है, जिसमें गैलरी को लेकर पड़ोसी शिवम रस्तोगी से विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इसी विवाद को लेकर 12 जून 2025 को शिवम रस्तोगी बिहारीपुर चौकी इंचार्ज योगेन्द्र सिंह व सिपाही हरिपाल सिंह के साथ मौके पर पहुंचा और उनके 17 वर्षीय नाबालिग भाई हर्षित रस्तोगी को बिना किसी आदेश के जबरन घर से उठा ले गया। चौकी ले जाकर उसका मोबाइल छीन लिया गया और मारपीट की गई। स्मिता का आरोप है कि जब वह चौकी पहुंची और इस बारे में पूछताछ की, तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी बदसलूकी की और मोबाइल छीनने का प्रयास किया। उन्होंने पूरी घटना का वीडियो साक्ष्य होने का दावा करते हुए बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने जनसुनवाई पोर्टल पर भी की, लेकिन कोतवाली प्रभारी ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि यदि कहीं और शिकायत की तो उन्हें, उनके पति और नाबालिग भाई को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। पीड़िता ने मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

विकसित भारत के अमृत काल पर भाजपा ने लगाई चौपाल

*मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों पर केंद्रित रहा जनसंवाद कार्यक्रम

कानपुर।

भारतीय जनता पार्टी रायपुरवा मंडल के अंतर्गत भन्नानपुरवा, शक्ति केंद्र पर विकसित भारत का अमृत काल एवं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा एक विशेष चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप उपस्थित रहे। चौपाल की अध्यक्षता रायपुरवा मंडल अध्यक्ष गौरव पांडे ने की। चौपाल को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष *प्रकाश पाल* ने कहा कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के हर वर्ग के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। चाहे वह गरीबों को पक्के मकान देने की योजना हो, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत या किसान सम्मान निधि ङ्क सभी योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत के भीतर विकास की नई गाथा लिखी है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को भी नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। आज भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और निर्णायक नेतृत्व वाला राष्ट्र माना जा रहा है। जिलाध्यक्ष *अनिल दीक्षित* ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक 'रोटी, कपड़ा और मकान' को केवल एक चुनावी नारा बनाकर रखा, जबकि भाजपा ने इन तीनों को हर गरीब तक वास्तविक रूप में पहुँचाया है। यही सुशासन की पहचान है। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने घर-घर संपर्क अभियान के तहत नागरिकों को मोदी सरकार की उपलब्धियों से संबंधित पत्रक वितरित किए । चौपाल में किशनलाल सुदर्शन महेश मिश्रा विनय त्रिपाठी देवांग शर्मा रवि शंकर हवेलकर अजय सिंह पुष्कर निगम कपिल गुप्ता किशन शुक्ला दिव्यांश मिश्रा प्रीति साहू सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, महिलाएं, युवा कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। यह जनसंवाद कार्यक्रम मोदी सरकार की जन-जन तक पहुंच बनाने की पहल का हिस्सा है, जो 11 वर्षों की जनकल्याणकारी नीतियों को सीधे जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा ने बताया आज पनकी मंडल,चुनीगंज मंडल ,कौशल पुरी मंडल के विभिन्न शक्ति केंद्रों पर चौपाल लगाई गई।

मा. मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद ने बरेली में मत्स्य पालक गोष्ठी को किया संबोधित

बरेली।

रोहिलखंड विश्वविद्यालय के सभागार में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मा. मत्स्य मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद ने बरेली मंडल स्तरीय मत्स्य पालक गोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मत्स्य बीज वितरण, तालाब विकास, नाव व इंजन क्रय पर अनुदान, मत्स्य आवास और बीमा योजनाएं जैसे कई कार्यक्रमों के जरिए मछुआ समाज को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को पारदर्शिता और त्वरित गति से मिले। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक मछुआ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। उन्होंने मत्स्य पालकों से संगठित होने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। डॉ. निषाद ने केंद्र सरकार द्वारा जारी जातीय जनगणना अधिसूचना को ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे निषाद, मल्लाह, केवट, कश्यप जैसे जलाशय आधारित वंचित समाजों की सही जनसंख्या सामने आएगी और उनकी राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक हिस्सेदारी तय हो सकेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा, ÷गिनती से ताकत मिलेगी और ताकत से बराबरी मिलेगी।÷ गोष्ठी में बरेली मंडल के विभिन्न जिलों से आए मत्स्य पालक, अधिकारी और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

शुभमन की टीम के सामने तीन विदेशी दौरे, द. अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का रास्ता कठिन

नई दिल्ली ।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 चक्र के समापन के साथ ही अब नए चक्र को लेकर बातें होनी शुरू हो गई हैं। इस चक्र को दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने नाम किया। तेम्बा बावुमा की टीम ने गत विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अब नए चक्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसकी शुरुआत 17 जून से हो जाएगी, जब श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें भिड़ेंगी। वहीं, टीम इंडिया 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ नए टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की शुरुआत करेगी। यह डबल्यूटीसी का चौथा संस्करण होगा। इस दौरान अगले दो साल में नौ टीमों के बीच कुल 71 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इस चक्र में कई टीमें बदलाव के दौर से गुजरेंगी और एक नई शुरुआत करना चाहेगी। इसमें टीम इंडिया भी शामिल है, जो नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में इस चक्र में उतरेगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद से भारतीय टीम बदलाव के दौर में है। वहीं, इंग्लैंड की टीम के लिए भी जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के बिना सफर आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को भी इस बार कठिन चुनौतियां मिली हैं और उनके लिए स्थिर बने रहना बड़ी चुनौती होगी। वहीं, पाकिस्तान को एक बार फिर आसान विदेशी दौरे मिले हैं, लेकिन उनके लिए इससे पार पाना बड़ी चुनौती होगी। पाकिस्तान की टीम 2023-25 डब्ल्यूटीसी चक्र में आखिरी यानी नौवें स्थान पर रही थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में सबसे ज्यादा 22 टेस्ट मैच खेलेगी। वहीं, इंग्लैंड की टीम 21 मैच खेलेगी। इसके बाद 18 मैचों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड को 16 और दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज को 14-14 टेस्ट खेलने हैं। पाकिस्तान की टीम 13 और श्रीलंका-बांग्लादेश को 12-12 टेस्ट खेलने हैं। 2025-27 चक्र में प्रतिस्पर्धा करने वाले नौ देशों के बीच खेली जाने वाली 27 टेस्ट सीरीज में से 17 सीरीज में केवल दो मैच होंगे, जबकि तीन मैचों की छह सीरीज होंगी। श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत और इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम इस चक्र में अपने अभियान की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से करेगी। इसकी शुरुआत 25 जून से होने जा रही है। वहीं, चैंपियन दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने 2025-27 डब्ल्यूटीसी चक्र की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ अक्तूबर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज से करेगी। कम टेस्ट मैच होने की वजह से दक्षिण अफ्रीका के दो टेस्ट सीरीज के बीच काफी गैप है। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून से होने जा रही है। इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 जुलाई से खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया घर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज खेलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट दो अक्तूबर से और दूसरा टेस्ट 10 अक्तूबर से खेला जाएगा। फिर भारतीय टीम घर पर ही दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। इसका पहला मुकाबला 14 नवंबर से और दूसरा मकाबला 22 नवंबर से खेला जाएगा।

एक नजर

हरभजन, युवराज और रैना की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने अवैध सट्टेबाजी एप्स के प्रमोशन मामले में की पूछताछ

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म की जांच का दायरा बढ़ाते हुए पूर्व क्रिकेटर और फिल्मी हस्तियों द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित किया है। ईडी ने 1&Bet, Pairplay, Parimatch और Lotus 365 सहित प्रतिबंधित सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के साथ प्रमोशनल लिंक की चल रही जांच के तहत पूर्व भारतीय क्रिकेटरों हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना के साथ-साथ अभिनेता सोनू सूद और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला से पूछताछ की है। एनडीटीवी प्रॉफिट के अनुसार ईडी एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि, ये सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म विज्ञापन अभियानों में 1&bat और 1&bat स्पोर्टिंग लाइन्स जैसे सरोगेट नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विज्ञापनों में अक्सर क्यूआर कोड शामिल होते हैं जो यूजर्स को सट्टेबाजी साइट्स पर ले जाते हैं जो भारतीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। कुछ मशहूर हस्तियों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है जबकि अन्य को जल्द ही नोटिस जारी किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये एंडोर्समेंट से कई भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं। इनमें इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मन लॉन्ड्रिंग एक्ट और बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट के साथ-साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा जारी किए गए परामर्श शामिल हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले ये दो खिलाड़ी हुए चोटिल, बीसीसीआई ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान

नई दिल्ली। भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर हैं जहां उसे इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। वहीं इसी दौरान भारतीय अंडर-19 टीम भी अपना दम दिखाएगी। आईपीएल में धमाकेदार खेल दिखाने वाले आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय अंडर-19 टीम इंग्लैंड के खिलाफ 24 जून से 23 जुलाई के बीच एक 50 ओवर का वार्म-अप मैच, पांच यूथ वनडे और दो मल्टी-डे मैच खेलेगी। इस दौरे से पहले जूनियर क्रिकेट कमेटी ने आदित्य राणा और खिलन पटेल की जगह डी दीपेश और नमन पुष्पक को टीम में शामिल किया है। दीपेश और नमन दोनों ही इस दौरे के लिए स्टैंडबाय खिलाड़ियों की सूची में थे। बीसीसीआई ने बताया कि आदित्य को पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है जबकि खिलन को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्लीसेंस में चल रहे हाई-परफॉर्मेंस कैंप के दौरान दाहिने पैर में स्ट्रैस रिएक्शन हुआ है। आयुष म्हात्रे को चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद इस सीरीज के लिए कप्तानी सौंपी गई है। मेगा ऑक्सन में अनसोल्ड रहने के बाद उन्हें घायल कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की जगह टीम में चुना गया था। जीटी के खिलाफ एक मैच बाकी रहते हुए म्हात्रे सीएसके के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 6 पारियों में 34.33 की औसत से 206 रन बनाए हैं।

अब चार दिन के होंगे टेस्ट मैच, इस नियम को कब से लागू करेगा आईसीसी? भारत समेत तीन टीमें रहेंगी अपवाद

दुबई । विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के आने के बाद से टेस्ट क्रिकेट का रोमांच दोगुना हो गया है। अब टीमों के बीच जीत को लेकर रोमांचक जंग देखने को मिलती है। हालांकि, इसे और रोचक बनाने के लिए आईसीसी प्लेइंग कंडीशन में बदलाव करने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) 2027-29 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में छोटे देशों के लिए चार दिवसीय टेस्ट मैचों को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें इसमें अपवाद रहेंगी। ये तीनों देश एक दूसरे के खिलाफ पारंपरिक पांच दिवसीय मैच खेलेंगे। मैचों की संख्या एक दिन कम करने का कदम एक महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। आईसीसी का मानना है कि इससे छोटे देशों को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट और लंबी सीरीज खेलने में मदद मिलेगी। द गार्जियन अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया है, पिछले सप्ताह लॉर्ड्स में डब्ल्यूटीसी फाइनल में चर्चा के दौरान आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने 2027-29 डब्ल्यूटीसी चक्र के लिए चार दिवसीय टेस्ट के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। इसकी चर्चा फाइनल के दौरान इसलिए हुई ताकि समय से इस नियम को मंजूरी मिल सके और इसके लिए नियम बनाएं जा सकें। इसमें कहा गया है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत को तब भी एशेज, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी और एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए पांच दिवसीय मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने की अनुमति होगी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की शुरुआत शुक्रवार को हेडिंग्ले में इंग्लैंड और भारत के बीच पहले टेस्ट मैच के साथ होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून से होने जा रही है। आईसीसी ने पहली बार 2017 में द्विपक्षीय मुकाबलों के लिए चार दिवसीय टेस्ट को मंजूरी दी थी। इंग्लैंड ने 2019 और 2023 में आयरलैंड के खिलाफ चार दिवसीय टेस्ट के बाद पिछले महीने ट्रेंट ब्रिज में जिम्बाब्वे के साथ चार दिवसीय मैच खेला था। रिपोर्ट के मुताबिक, %कई छोटे देश समय और लागत के कारण टेस्ट मैचों की मेजबानी करने से कतराते हैं, लेकिन चार दिवसीय क्रिकेट की ओर कदम बढ़ाने से तीन टेस्ट मैचों की पूरी सीरीज तीन सप्ताह से भी कम समय में खेली जा सकेगी। रिपोर्ट में कहा गया है, चार दिवसीय टेस्ट मैचों में समय की बर्बादी को कम करने के लिए एक दिन के अंदर खेल के समय को बढ़ाकर प्रतिदिन न्यूनतम 98 ओवर कर दिया जाएगा। मौजूदा पांच दिवसीय टेस्ट में एक दिन में अधिकतम 90 ओवर गेंदबाजी होती है। रिपोर्ट में कहा गया है, पिछले सप्ताह लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोमांचक फाइनल में विश्व चैंपियन बनने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के नीरस कार्यक्रम ने इस मुद्दे को और उजागर किया और इसके बाद बदलाव की जरूरत महसूस की गई। हालांकि, 2025-27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पांच दिवसीय मैचों के मौजूदा प्रारूप के तहत जारी रहेगी। इसकी शुरुआत मंगलवार को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज से होगी। 2025-27 चक्र में प्रतिस्पर्धा करने वाले नौ देशों के बीच खेली जाने वाली 27 टेस्ट सीरीज में से 17 सीरीज में केवल दो मैच होंगे, जबकि तीन मैचों की छह सीरीज होंगी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत सभी एक-दूसरे के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगे।

आरसीबी को चैंपियन बनाने वाली ऑलरॉउंडर का वनडे क्रिकेट से संन्यास, टी20 में जारी रहेगा खेलना

नई दिल्ली।महिला टीम की कप्तान सोफी डिवाइन आगामी विश्व कप के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लेंगी. यह टूर्नामेंट इसी साल भारत और श्रीलंका में खेला जाना है. सोफी को महिला क्रिकेट में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है. उन्होंने 152 वनडे में 31.66 की औसत और आठ शतकों की मदद से 3990 रन बनाए हैं. इसके अलावा 146 टी20 इंटरनेशनल मैचों में एक शतक के साथ 3431 रन भी बनाए हैं. उन्होंने वनडे और टी20 में क्रमशः 107 और 119 विकेट लिए हैं. 35 वर्षीय सोफी डिवाइन ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. यानी इस तरह वे उन चुनिंदा क्रिकेटरों में शामिल हो जाएंगी जिन्होंने 300 से अधिक वनडे और टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं लेकिन उनके खाते में एक भी टेस्ट मैच दर्ज नहीं है. न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा मंगलवार को जारी बयान में डिवाइन ने कहा, 'मुझे लगता है कि मेरे लिए फैसला करने का यह सही समय है. मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इस फैसले पर पहुंचने में मेरी मदद की. इसका मतलब है कि मैं अब भी न्यूजीलैंड की तरफ से खेल सकती हूं. सोफी डिवाइन का यह बयान न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा 17 केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की घोषणा से पहले आया है. अनुबंधित खिलाड़ियों की घोषणा बुधवार को की जाएगी. डिवाइन टी2महिला वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लेंगी सोफी.0 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए उपलब्ध रहेगी, लेकिन उन्हें केंद्रीय अनुबंध नहीं दिया जाएगा. सोफी डिवाइन विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए खेलती रही हैं. आरसीबी विमेंस ने डब्ल्यूपीएल का पहला खिताब 2024 में जीता था. उन्होंने डब्ल्यूपीएल में 18 मैच में 268 रन बनाए और 9 विकेट झटके हैं.

रोमांच की सारी हदें हुई पार! नीदरलैंड-नेपाल के बीच तीन सुपरओवर में आया फैसला, बना नया रिकॉर्ड

ग्लास्गो । नीदरलैंड ने ग्लास्गो में टी20 अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय क्रिकेट सीरीज के मैच में नेपाल को तीसरे सुपर ओवर में हरा कर नया रिकॉर्ड बनाया। टी20 या लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब किसी मैच का परिणाम तीसरे सुपर ओवर में निकला। इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। फैंस दांतों तले अंगुली दबाते हुए मैच देखते रहे। मेजबान स्कॉटलैंड इस टी20 त्रिकोणीय सीरीज की तीसरी टीम है।

नेपाल के नंदन यादव ने इस तरह पलटा मैच

सोमवार की रात को खेले गए इस मैच में तीसरे सुपर ओवर में माइकल लेविट ने छक्का लगाकर आखिर में नीदरलैंड को जीत दिलाई। नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 152 रन बनाए। एक समय उसकी जीत सुनिश्चित लग रही थी क्योंकि नेपाल को आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। नेपाल के निचले क्रम के बल्लेबाज नंदन यादव ने हालांकि अंतिम ओवर में दो चौके लगाए। उन्होंने आखिरी गेंद पर भी चौका लगाया जिससे नेपाल आठ विकेट पर 152 रन बनाकर स्कोर बराबर करने में सफल रहा।

पहला और दूसरा सुपरओवर हुआ टाई

कुशाल भुर्टेल ने 18 रन बनाकर नेपाल को पहले सुपर ओवर में 19 रन तक पहुंचाया, लेकिन नीदरलैंड के सलामी बल्लेबाज मैक्स ओडॉव ने पांचवीं और छठी गेंद पर क्रमशः छक्का और चौका लगाकर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद नीदरलैंड ने दूसरे सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी की और 17 रन बनाए। हालांकि, नेपाल के दीपेंद्र सिंह एयरी ने काइल क्लेन की आखिरी गेंद को छक्के के लिए भेज कर मैच को नए मोड़ पर खड़ा कर दिया। दूसरा सुपर ओवर भी टाई रहा।

तीसरे सुपरओवर में एक भी रन नहीं बना पाया नेपाल

तीसरे सुपर ओवर में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी की और एक भी रन नहीं बना पाया। नीदरलैंड के ऑफ स्पिनर जैक लायन कैशेट ने चार गेंदों में बिना कोई रन दिए दो विकेट लेकर नेपाल का ओवर जल्दी समाप्त कर दिया। सुपर ओवर में दो विकेट गिर जाने पर पारी समाप्त हो जाती है। इसके बाद नीदरलैंड को इस तरह से मैच जीतने के लिए सिर्फ एक रन की जरूरत थी, लेकिन लेविट ने संदीप लामिछाने के ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़कर मैच का शानदार अंत किया।

इजरायल-ईरान युद्ध में इस एथलीट की दर्दनाक मौत, ट्रेनिंग से लौट रहे थे घर

इजरायल ।

इजरायल और ईरान के बीच जंग गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ हमले जारी है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखकर लगता नहीं कि जंग जल्द खत्म होगी। वहीं इस युद्ध में दोनों ही तरफ से कई लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल, इजरायल की ओर से हुए हमले में ईरान के सैन्य कमांडरों, वैज्ञानिकों और नागरिकों की मौत हुई है। वहीं राष्ट्रीय पैडल टीम के एक प्रमुख सदस्य पारसा मंसूर की मौत हो गई है। पारसा मंसूर की मौत उस वक्त हुई जब वह ट्रेनिंग के बाद घर लौट रहे थे और मिसाइल हमलों में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं ईरानी अधिकारियों ने इजरायल के इस कृत्य के रूप में कड़ी निंदा करते हुए निर्णायक जवाब देने की कसम खाई है। ईरानी टेनिस महासंघ और खेल समुदाय ने मंसूर की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उनके परिवार और साथियों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अपने समर्पण और केल कौशल के लिए पहचाने जाने वाले मंसूर को खेल में उभरता सितार माना जाता था। बता दें कि, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इजरायल की ओर से 13 जून की सुबह तेहरान और अन्य शहरों में कई स्थानों को निशाना बनाया गया। इजरायल का मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। इजरायल और अमेरिका ईरान को कई बार परमाणु कार्यक्रम बंद करने को कह चुका है। ऐसे में इजरायल के निशाने पर ईरान के परमाणु, सैन्य, तेल के डिपो, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य खुफिया ठिकाने हैं। वहीं रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की तरफ से नागरिक को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। मुख्य रूप से ईरान तेल अवीव पर अधिकतर मिसाइलें दाग रहा है। इसका असर तेल अवीव स्थित अमेरिका के दूतावास पर भी प्रभाव पड़ा है।

विराट के दोस्त ने भरा बीबीएल खेलने का पर्चा, आईपीएल में 4 टीमों के लिए कर चुके हैं गेंदबाजी

नई दिल्ली। क्रिकेट की दुनिया में टी-20 लीग के बढ़ते वर्चस्व और तेजी से फैलते इस फॉर्मेट के साम्राज्य में अब धीरे धीरे भारतीय खिलाड़ियों की इंट्री होना शुरु हो चुका है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को बताया कि भारत के पूर्व तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने पुरुषों की बिग बैश लीग के ड्राफ्ट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है,जबकि 15 अन्य खिलाड़ियों ने महिला टूर्नामेंट के लिए ऐसा ही किया है.पिछले साल नवंबर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले भारत के लिए तीन वनडे और इतने ही टी20 मैच खेलने वाले कौल गुरुवार को यहां होने वाले बीबीएल ड्राफ्ट के लिए खुद को पंजीकृत कराने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं. इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन दुनिया भर के 600 से अधिक खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने लीग के लिए खुद को पंजीकृत कराया है. अगर एंडरसन चुने जाते हैं, तो वह 43 साल की उम्र में लीग में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगे. बिग बैश खेलने का प्रयास कर रहे सिद्धार्थ कौल भारत के उन तेज गेंदबाजों में से है जो सीमित स्किल के बाद अपनी मेहनत से पहले इंडिया के लिए 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेल चुके हैं और वो इंडियन प्रीमियर लीग में भी लगातार खेलते रहे . सिद्धार्थ सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर समेत कई टीमों का हिस्सा रह चुके हैं. लेकिन आईपीएल 2024 के ऑक्शन में उन्हें किसी टीम ने नहीं खरीदा था. वे विराट कोहली की कप्तानी वाली अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम इंडिया का हिस्सा रह चुके हैं. वे और कोहली 2008 में एक ही टीम का हिस्सा थे. सिद्धार्थ कौल ने सीनियर टीम इंडिया के लिए 2018 में डेब्यू वनडे मैच खेला. वहीं इसी साल ही डेब्यू टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेला सिद्धार्थ को 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने टीम में शामिल किया. उन्होंने इससे पहले 2013 में आईपीएल डेब्यू मैच खेला था. सिद्धार्थ हैदराबाद के साथ-साथ कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लिए खेल चुके हैं. सिद्धार्थ ने आईपीएल में अभी तक 54 मैच खेले हैं. इस दौरान 58 विकेट झटके हैं. उनका एक मैच में 29 रन देकर 4 विकेट लेना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है. कनिका आहूजा, जो महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलती हैं और जिन्होंने इस साल की शुरुआत में भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, भारत की 15 महिला खिलाड़ियों में शामिल हैं.अन्य भारतीय महिला खिलाड़ियों में जेमिमा रोड्रिग्स, शिखा पांडे, राधा यादव और यास्तिका भाटिया शामिल हैं, जो पहले डब्ल्यूबीबीएल में खेल चुकी हैं.इस सूची में एस मेघना, अरुंधति रेड्डी, प्रतीक रावल, अंडर-19 टी20 विश्व कप विजेता कप्तान निकी प्रसाद, उमा छेत्री, काशवी गौतम, प्रिया मिश्रा और कुछ अन्य खिलाड़ी भी शामिल हैं.

अश्विन पर लगा गंभीर आरोप, केमिकल युक्त तौलियों से बॉल से छेड़छाड़ का आरोप, टीएनपीएल ने मांगे सबूत

नई दिल्ली । भारतीय टीम के दिग्गज गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन इन दिनों मुश्किलों में फंस गए है। आर अश्विन पर तमिलनाडु प्रीमियर लीग (टीएनपीएल) के दौरान गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आर अश्विन पर ये गंभीर आरोप मदुरै पैंथर्स ने डिंडीगुल ड्रैगन्स ने लगाया है। टीम ने अश्विन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व भारतीय स्पिनर ने 14 जून को उनके मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की थी। टीएनपीएल आयोजकों ने दावों के समर्थन में साक्ष्य की मांग की है। मदुरै पैंथर्स ने डिंडीगुल ड्रैगन्स पर रासायनिक उपचार वाले तौलिये का उपयोग करने का आरोप लगाया, जिससे गेंद भारी हो गई और बल्ले से टकराने पर धातु जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। इन गंभीर आरोपों के जवाब में टीएनपीएल के सीईओ प्रसन्ना कन्नन ने कहा कि यद्यपि शिकायत स्वीकार कर ली गई है, फिर भी मदुरै को सबूत देना होगा। उन्होंने कहा, ''उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। यद्यपि उन्हें खेल के 24 घंटे के भीतर कोई भी शिकायत दर्ज करानी होती है, फिर भी हमने इसे स्वीकार कर लिया है और उनसे अपने आरोपों का सबूत प्रस्तुत करने को कहा है। यदि हमें उनके आरोपों में कोई सच्चाई लगी तो हम एक स्वतंत्र समिति गठित करेंगे। पर्याप्त सबूतों के बिना किसी खिलाड़ी और दूसरी फ्रेंचाइजी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाना गलत है। प्रसन्ना ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, अगर वे कोई सबूत नहीं देते हैं, तो मदुरै को उचित

प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। मदुरै फ्रेंचाइजी के सीओओ एस महेश ने एक पत्र में शिकायत का विवरण देते हुए कहा कि चेतावनी के बावजूद डिंडीगुल ड्रैगन्स ने गेंद से छेड़छाड़ जारी रखी। डिंडीगुल ड्रैगन्स के खिलाफ हमारे हालिया मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया। महेश ने अपने पत्र में लिखा, बार-बार चेतावनी के बावजूद डिंडीगुल की टीम ने गेंद के साथ छेड़छाड़ की और ऐसे तौलिये का इस्तेमाल किया जो रसायनों से उपचारित प्रतीत हो रहे थे। बारिश के कारण कुछ समय के लिए विलंबित हुए इस मैच में मदुरै ने 20 ओवर में 150/8 का स्कोर बनाया, जिसे डिंडीगुल ने 12.3 ओवर में नौ विकेट रहते हासिल कर लिया। हालाँकि अश्विन ने कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ओपनर के तौर पर 49 रन बनाए। मानसून के मौसम में गीली परिस्थितियों को देखते हुए, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन, फ्रेंचाइजियों को गेंद सुखाने के लिए तौलिए उपलब्ध कराता है, जो अंपायरों के सामने किया जाना चाहिए। कन्नन ने टीआईई से कहा, उन्हें टीएनपीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए तौलिये का उपयोग करके ही गेंद को सुखाना पड़ता है। और जब भी गेंद पर छक्का लगता है या आउट होने और ओवर-ब्रेक के तुरंत बाद, अंपायर नियमित रूप से गेंद की जांच करते हैं और उन्हें उक्त मैच के दौरान गेंद में कोई समस्या नहीं मिली। कन्नन ने मदुरै फ्रेंचाइजी से अनुरोध किया है कि वे अपने आरोपों के समर्थन में कोई भी ठोस सबूत उपलब्ध कराएं।